advantage. The relevant facts in regard to the investment approval accorded for the Project are as under:

An MOU was signed in July, 1994 between Government of India, M/s Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (RCF) and Krishak Bharati Cooperative Ltd. (KRIBHCO) on the Indian side and Sultanate of Oman and Oman Qil Company on the Omani side to set up an Ammonia Urea Complex in Oman as a Joint Venture between Oman Oil Company and RCF/KRIBHCO.

Prior to the registration of a joint venture company (JVC) in February 1998, all the decisions relating to the Joint Venture project were taken by a Joint Management Committee (JMC), which had three members each from the Indian and the Omani sides.

Since then, all the decisions relating to the Joint Venture are being taken by the board of the JVC, which also has three members each from the Indian and the Omani sides.

Approval for investment of US$ 69 million each by RCF and KRIBHCO in the equity of the JVC was accorded by the Government in December 1997 after considering all the aspects relevant to the decision taken by the project sponsors in regard to the arrangements for the execution of the project.

The Joint Venture Company has taken effective steps towards mobilisation of international finance for the implementation of the project.

Apart the MOU referred to above, no agreement has been signed between Government of India and Oman Oil Company.

Subsidy Payments to Urea Manufacturers

271. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have modified thenorms, declared in October, 1997 and supposed to be continued upto March, 1998, for subsidy payments to urea manufacturers;

(b) if so, the reasons for the sudden modifications;

(c) whether the modified norms are made applicable to domestic manufacturers including large scale manufacturers; and

(d) the results of the modifications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (d) On consideration of the representations of the fertiliser industry regarding the impact on the cost of production of the increase in the price of hydrocarbons and the wide variations in the turn around programmes of urea untis, the following modifications were made in the restriction on the off-take of urea introudced in October, 1997.

(i) The off-take restriction was made applicable to units having a retention price of Rs. 7300 per tonne or above instead of Rs. 7000 per tonne as initially decided.

(ii) The methodology for computation of the proportionate annual installed capacity was revised to take into account the actual number of stream days of operation and the effective daily rated capacity.

The modified as well as the original criterion was applicable to all urea units whose retention price was above the relevant cut off point.

आई.डी.पी. एल. को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना

272. **श्री मनोहर कांत ध्यानी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश में स्थित आई.डी.पी.एल. के कारखाने का निर्माण सत्तर के दशक में वृक्षाविहीन भूमि में किया गया था;

(ख) क्या कालोनी सहित संबंधी ये सभी व्यवस्थाएं नाममात्र के पट्टे पर ली गई वन भूमि पर की गई है;

(ग) क्या सरकार इस भूमि को आई.डी.पी.एल. के नाम अंतरित कर उसे श्रेणी "क" के स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तब तक, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.ए.के.पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) भाग (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

ऋषिकेश स्थिति आई.डी.पी.एल. कारखाने का पुनर्जीवित किया जाना

237. **श्री मनोहर कांत ध्यानी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश में स्थिति आई.डी.पी.एल. के कारखाना लम्बे समय से बन्द है;

(ख) क्या सरकार इस कारखाने के पुनर्जीवन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इसके कर्मचारियों को लम्बे समय से वेतन नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो पुनर्जीवन योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी और इसके कर्मचारियोम को कब तक वेतन मिलना आरम्भ हो जाएगा; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और तत्संबंधी व्यापक ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.ए.के. पटेल) : (क) जी, हां आई.डी.पी. एल. कारखाना ऋषिकेश में अक्टूबर, 1996 से उत्पादन बन्द कर दिया गया है।

(ख) से (ड़) आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों को 15.03.1998 तक उनके शुद्ध वेतन का भुगतान किया जा चुका है। आई.डी.पी.एल. को मई 1992 में बी. आई.एफ.आर. को भेजा गया था। इसे 12.08.92 को औपचारिक रुप से रूरश घोषित किया गया था। आई.डी.पी.एल. प्रबन्धक द्वारा तैयार किया गवर पुनरुद्धार पैकेज और औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई द्वारा पुनरीक्षा की गई थी, को 10.02.94 को बी.आई.एफ.आर द्वारा अनुमादित किया गया था। चूंकि आई.डी.पी.एल. वर्ष 1994-95 पुनरुद्धार प्रचालन के प्रथम वर्ष में उत्पादन, बिक्री और लाभदेयता का लक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर सका। कम्पनी ने पैकेज में संशोधन का सुझाव दिया । अत: सरकार ने संशोधनों की तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण के लिए बी.आई.एफ.आर. से सम्पर्क करने का निर्णय किया था। बी.आई.एफ.आर. ने आई.डी.पी.एल. के लिए एक दीर्घकालीन पुनर्वास उपायों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.बी.बी.आई.) मुम्बई को संचालन एजेंन्सी नियुक्त किया। संचालन एजेन्सी की रिपोर्ट आई.टी.पी.एल. प्रबन्धन और कर्मचारियों से सम्पर्क करके सरकार द्वारा जांच की जा रही है। तथापि पुनर्वास पैकेज की अन्तिम स्वीकृति रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपलब्ध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) के अधीन निर्धारित प्राधिकारी औद्योगिक और वित्तीय पुनरुद्धार बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के समक्ष प्रस्तुत विचार-विमर्श पर निर्भर करेगा।

Production and demand of urea

274. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the quantity of urea produced in the country during last three years, year-wise in Govemment sector and private sector;

(b) the total demand of urea in the country and how the deficit is managed;

(c) whether most of the fertilizers unit have failed to achieve capacity utilisation if so, the reasons therefore and the steps taken to improve the same;

(d) whether the ministry's attention has been drawn to the news-item captioned "Cheaper feedstock, urea price decontrol must for shorting up fertilizer projects" appeared in the Hindustan Times dated April 29, 1998; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) The year-wise production and demand of urea during the last three years have been as under:

(Lakh Tonnes)

Year	Sector	Production	Consumption
1995-96	Public	52.09	
	COOP.	36.20	
	PVT.	69.91	
	TOTAL	158.20	179.09
1996-97	Public	47.30	
	COOP.	34.62	
	PVT.	74.28	
	TOTAL	156.20	190.25
1997-98	Public	60.07	
	COOP	46.24	
	PVT.	79.65	
	TOTAL:	185.96	200.08 (estimated)